forest clearance in respect of Sriram Right Bank Canal Project. The status of appraisal of other projects remains practically the same and the State Government is required to comply with the observations of Central appraising agencies.

(d) and (e) The status of appraisal of pending projects is periodically reviewed by the officials of Central Water Commission with the officials of State Government. Such a review was last held on 15.12.1995. The status of appraisal of Andhra Pradesh was also reviewed by the Secretary. Ministry of Water Resources on 9th, 12th and 20th March, 1996. Periodical reminders are also issued.

Security threat posed by Cellular Phones

3104. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the use of Cellular Phones in four metropolitan cities is posing threat to national security;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have decided to monitor Cellular Services; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) The licenses issued to the Cellular Operators provide for adequate safeguards for the national Security.

(b) Does not arise in view of (a).

(c) Cellular service has to provide monitoring as standard arrangement.

(d) Eight numbers of Cellular licenses in four metro cities of Delhi, Calcutta, Bombay & Madras have been asked to provide circuits for monitoring for calls by authorised Govt. Security agencies.

क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को मुआवजा

3105. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन केबल बिछाने से सड़कों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु लोक निर्माण विभाग ने कुल कितनी धनराशि की मांग की थी;

(ख) कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और कितने का भुगतान किया जाना शेष है; और

(ग) शेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (संचार मंत्री): (क) सड़क काटने तथा इसे पुन: ठीक करने हेतु भुगतान सदैव, केबल बिछाने का कार्य चालू होने से पहले, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा सूचित दरों के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को कर दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए, सड़क को पुन: ठीक करने के लिए किये गये अग्रिम भुगतान की राशि 892 लाख रु० है तथा अभी तक वर्ष 1996-97 हेतु यह राशि शून्य है।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरिपुलों के निर्माण के लिये प्राप्त प्रस्ताव

3106. **श्री अजीत जोगी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरिपुलों के निर्माण के लिए राज्यों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्गों-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक ऐसे कितने प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं; जिनमें निर्माण कार्य प्रगति पर हैं;

(घ) ऐसे प्रस्तावों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी मंजरी दी जानी रहती है;

(ङ) इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्य-वार कितने उपरिपुलों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन):
(क) से (च)

क्रम सं॰	राज्य का नाम	रा.रा. सं॰	प्रस्तावों की सं॰	अनुमोदित/ स्वीकृत प्रस्तावों की सं॰	टिप्पणी
1.	कर्नाटक	4	1	1	22.8.96 को स्वीकृत
2.	महाराष्ट्र	4	1		सं. 4-निधियों की कमी की
		6	3		वजह से अनुमोदित नहीं की गई।
		3	2		सं॰ 3-बी ओ टी के तहत
		7	1		ली जानी है।
3.	गुजरात	8	1		वार्षिक योजना 1996-97 में दी गई, है।
4.	राजस्थान	11	1		सं॰ 1-निधियों की कमी की
		8	1		वजह से अनुमोदित नहीं की गई। सं॰ 2- बी ओ टी के तहत ली जानी है।
5.	मध्य प्रदेश	3	11		1- निधियों की कमी की वजह से अनुमोदित नहीं की गई।
6.	असम	31	1		वार्षिक योजना में नहीं दी गई।
7.	उड़ीसा	5	1		विश्व बैंक पैकेज 11 के तहत स्वीकृत।
8.	पश्चिम बंगाल	2	4		विश्व बैंक पैकेज 11/ए डी बी परियोजना के तहत स्वीकृत।
9.	बिहार	31	1		
		2	1		बी ओ टी के तहत ली जानी है।

पंजाब में बुनकरों के लिये आवासों का निर्माण करने के लिये सहायता

3107. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में पंजाब के बुनकरों के लिये आवासों का निर्माण करने के लिये वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता की कितनी धनराशि का अब तक उपयोग किया गया है और कितने लोगों को अब तक आवास उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) उपयुर्क्त वित्तीय सहायता में से बची हुई धनराशि का उपयोग करके राज्य के बुनकरों के लिये आवासों के निर्माण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में हथकरघा बुनकरों को कार्यशाला सह आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता देने हेतु राज्यवार प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायता जारी की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Peace Accord with Underground Guerillas in the North-East Region

3108. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of peace accords signed for bringing peace in the North-East region between the Central Government and undergound guerillas;